

Civil Service Exam

भारत की शासन प्रणाली नोट्स



Head- Akash Pal

96968179263

दोस्तों यह जिंदगी है हार-जीत के लिए पैदा नहीं हुए हो, कुछ अच्छा कार्य के लिए भगवान ने आपको भेजा है व्यर्थ न करें यह जीवन।

Daily Download More PDF
Google- www.akashpal.com

सफलता आपकी, साथ हमारा

Dear Friends, यदि आपको किसी भी परीक्षा के लिए Subject Wised Coaching के Handwriting Notes की आवश्यकता हो या Previous Year Paper की आवश्यकता हो तो हमें वाट्सएप कर सकते है आपको तत्काल Handwriting नोट्स PDF Format में उपलब्ध कराये जाएंगे

Contact Us- **8887120469**

WhatsApp- **7275751297**

UPSC (IAS/IPS) & State PCS

“मौका Hard Work का नहीं Smart Work का है”
 ‘दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जो अपने अपने पूरे करते हैं उन 10% लोगों में आपकी गणना होनी चाहिए’

★ History

- प्राचीन भारत का इतिहास
- मध्यकालीन भारत का इतिहास
- आधुनिक भारत का इतिहास
- NCEAT Based history Notes (Class 6th to 12th)
- विश्व का इतिहास
- प्राचीन से वर्तमान तक सभी महत्वपूर्ण घटनाएं
- Spectrum History Notes
- आजादी के बाद भारत का परिदृश्य

★ Geography

- भारत का भूगोल
- विश्व का भूगोल
- भारत का भौतिक भूगोल
- NCEAT Based Geography Notes (Class 6th to 10th)
- मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

★ Polity

- भारतीय राज्य व्यवस्था
- भारतीय शासन
- NCEAT Based Politics Notes (Class 6th to 10th)

★ Economics

- भारत की अर्थव्यवस्था
- विश्व की आर्थिक स्थिति
- आर्थिक सर्वेक्षण व सिद्धांत
- बजट का आंतरन व आंकड़े
- प्रमुख राज्यों का आर्थिक बजट
- NCEAT Based Economy Notes (Class 11th and 12th)

★ Environment

- पर्यावरण एवं परिसंस्थितिकी तंत्र
- पर्यावरण संबंधित सम्मेलन, सूचकांक व पुरस्कार
- जनसंख्या, नगरीकरण व सिद्धांत
- पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवस व कानून
- जैव विविधता

★ Science

- सामान्य विज्ञान NCEAT Based Notes (Class 9th and 10th)
- सामाजिक विज्ञान NCEAT Based Notes (Class 6th to 10th)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Sci & Techno.)

★ Current Affairs

- राष्ट्रीय घटनाक्रम (पिछले 12 महीने का)
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम (पिछले 6 महीने का)
- खेल घटनाक्रम (पिछले दो साल का)
- प्रमुख राज्यों की सामसामयिकी

★ Imp. Topic

- भारतीय समाज (Indian Society)
- भारत की आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)
- अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relation)
- जल वायु परिवर्तन (Climate Change)
- भारतीय कला एवं संस्कृति (Arts & Culture)
- सामिक पत्रिकाएं (योजना व कुरुक्षेत्र)
- राष्ट्रीय आंदोलन व भौतिक विकास
- राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दे

→ **संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स - 1000 ₹ (PDF Format)**

Note- दोस्तों Notes बनाने में समय लगता है इसीलिए फ्री नोट्स उपलब्ध करना संभव नहीं, भारत में UPSC के लिए मराठूर कोचिंग के Notes का अध्ययन कर यह इच्छा नोट्स तैयार किया गया है, संपूर्ण नोट्स पढ़ने के पश्चात् इतना दावा है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न इस नोट्स से बाहर नहीं आयेगा

Payment Process-

- Phone Pe- 8887120469
- Google Pay- 8887120469
- Paytm- 9839600351
- UPI- SKYEDU@Centralbank
- Account No.- 3201090371
- Account Name- VIKAS PAL
- IFSC Code- CBIN00283930
- Bank Name- Central Bank of India

→ Payment करने के पश्चात् Screenshot (Payment Slip) हमें 8887120469 पर वाट्सएप करें

Notes की खासियत-

- स्वच्छ एवं सुंदर हस्तलेखन
- स्पष्ट भाषा व Basic Concept का मिश्रण
- प्रत्येक पेज की सुव्यवस्थित ढंग से Scanning
- बेहतर पुस्तक के व कोचिंग नोट्स को अध्ययन कर तैयार किया

Note- घर बैठे तैयारी करने का बेहतरीन मौका, इस ग्रंथाई के दौर में बहुत कम मूल्य में विश्वास के साथ हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा “अभी नहीं तो फिर कभी नहीं”

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

अनुसूची	विषय
पहली अनुसूची	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
दूसरी अनुसूची	राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, राज्य सभा सभापति / उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम और उच्च न्यायालय के -यायाधीशों और CAG के <u>वेतन और भत्ते</u>
तीसरी अनुसूची	विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली <u>शपथ</u>
चौथी अनुसूची	राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए <u>राज्यसभा में सीटों का आवंटन</u>
पाचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
छठी अनुसूची	<u>असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम</u> राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
सातवी अनुसूची	विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1. संघ सूची 2. राज्य सूची 3. समवर्ती सूची
आठवी अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त <u>भाषाएँ (मूल-14 फिलहाल-22)</u>
नवी अनुसूची	कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का <u>विधिमाम्यकरण</u>
दसवी अनुसूची	<u>दल-बदल अधिनियम</u>
ग्यारहवी अनुसूची	<u>पंचायतों</u> की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारी - 29 विषय
बारहवी अनुसूची	<u>नगरपालिका</u> की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारी - 18 विषय

www.akashpal.com

अनुच्छेद 1 - 'भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा'

राज्यों का संघ कहे जाने का तात्पर्य है कि यह संघ किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है बल्कि यह भारतीय जनता द्वारा चुने गये संविधान सभा के निर्णय का परिणाम है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राज्य स्वेच्छा से संघ से पृथक् नहीं हो सकता है और न ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर सकता है।

अनुच्छेद 2 - नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान

अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियाँ प्रदान करता है -

- नये राज्य को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति (जो पहले से अस्तित्व में है)
- नये राज्यों को गठन करने की शक्ति (जो अस्तित्व में नहीं है)

www.akashpal.com

अनुच्छेद 3 - नये राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा तथा नाम में परिवर्तन

इसके तहत संविधान, संसद को यह अधिकार देता है कि वह नये राज्य बनाये, उसमें परिवर्तन करे, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4 - इसके अनुसार -

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं होगा। अर्थात् साधारण बहुमत से नये राज्यों का गठन किया जा सकता है।

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

1. अनुच्छेद-14 → "विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण"

इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनायेगा और उन पर एक समान लागू करेगा।
विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन से तथा विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में प्रदत्त अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 14 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आधारभूत हार्च माना है जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहाँ समान एवं असमान के बीच अलग-2 व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन-देन के लक्ष्यगत कार्यों को स्वीकृत करता है।

www.akashpal.com

2. अनुच्छेद-15 → "धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध"

अनुच्छेद 15(1) - राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। (अन्य आधार पर भेद हो सकता है)

अनुच्छेद 15(2) - नागरिकों के मह्य केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या ~~व्यक्ति~~ दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, साधारण तथा जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों के उपयोग के संबंध में भेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15(3) - राज्य द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 15(4) - शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति और जनजातियों के ~~संबंध~~ के संबंध में विशेष प्रावधान (आरक्षण की व्यवस्था)

अनुच्छेद 15(5) - शिक्षण संस्थाओं में (जैसे सरकारी व गैर-सरकारी प्रायः सभी शामिल) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्ति या पदों के आरक्षण की सुविधा यह प्रावधान 93वाँ संशोधन, 2005 के द्वारा शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं (IIT, IIM) में 27 सीटें आरक्षित की गयी हैं।

3. अनुच्छेद-16 → "लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता"

अनुच्छेद 16(1) - राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16(1) और 16(2) ^{लोक} नियोजन के विषय पर भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।

SKYEDUCATION

यदि आप परीक्षा में वाकई सफल होना चाहते हैं एक बार हमारा हस्तलिखित नोट्स पढकर परीक्षा हॉल में जाइये परीक्षा में एक भी प्रश्न हमारी नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा (100% गारंटी) नोट्स बनाने में समय लगता है इसलिए फ्री में उपलब्ध कराना संभव, परंतु सभी मध्यवर्गीय स्टूडेंट्स के लहजे से नोट्स बहुत कम मूल्य में आपको वाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा यदि आप घर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सुविधा भी उपलब्ध है (अतिरिक्त शुल्क लागू)

Our Best Performance-

- Complete Vedio Paid Course (Very Low Price)
- Complete Handwriting Notes (PDF Format)
- Notes Home Delivery Available (Extra Pay Apply)

Online Paid Classes या नोट्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो (No. #1 Coaching)

Whatsapp Msg/Call- 8887120469 (4.1 Star Google Rating)

महान्यायवादी [Attorney General]

- संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- * नियुक्ति एवं कार्यकाल -
 - महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक बना रह सकता है।
 - इसकी नियुक्ति की वही योग्यताएँ हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जरूरी हैं।
 - इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है।
- * कार्य एवं शक्तियाँ - www.akashpal.com
 - भारत सरकार या राष्ट्रपति को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये हों।
 - यह भारत सरकार की तरफ से भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है।
 - यह संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा यह संसद की समितियों में सदस्य के रूप में शामिल होता है और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेता है।
 - अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
 - अनुच्छेद 105 के तहत अन्य संसद सदस्यों की भांति उसकी संसद या समिति में कही गयी किसी बात के लिए उसे न्यायालय में उत्तरदायी नहीं धराया जा सकता।
 - महान्यायवादी को सहयोग देने के लिए सालिसीटर जनरल (कानूनी सलाहकार) का पद सृजित किया गया है।
- महान्यायवादी आपराधिक मामलों में निजी तौर पर विधिक सलाह नहीं दे सकता।
- यह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।

राज्यसभा की संरचना

* अनुच्छेद 80 - 'राज्यसभा की संरचना'

अधिकतम संख्या - 250 (238 राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)

वर्तमान - 245 सदस्य (229 राज्य से + 4 केंद्र शासित प्रदेश से + 12 मनोनीत)

→ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। (अनुच्छेद 80(4))

→ संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। (अनुच्छेद 80(2))

→ राज्यसभा में राज्यों को स्थान का आवंटन 'जनसंख्या के आधार' पर होता है। इसीलिए प्रत्येक राज्य में अलग-2 सीटें होती हैं।

→ राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

www.akashpal.com

राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता

* अनुच्छेद 84 - 'राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता'

- वह भारत का नागरिक हो
- 30 वर्ष आयु हो।
- वह संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यता रखता हो।

अयोग्यता (निर्हताएं)

संवैधानिक आधार पर (राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश पर)	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आधार पर (राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश पर)	आपराधिक कानून (उच्चतम न्यायालय द्वारा)	दल-बदल के आधार पर (संबंधित सदन के अध्यक्ष or सभापति द्वारा)
→ यदि वह लाभ का पद धारण करता है। → घोषित दिवालिया है।	→ भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो। → किसी निगम में जिसमें सरकार का 25% से अधिक अंश हो, लाभ का पद धारण करता हो।		→ अगर निर्दलीय चुनावका सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता हो। → स्वच्छासे राजनीतिक दल का त्याग करने पर

* उच्च-यायालय *

अनुच्छेद 214 - 'राज्यों के लिए उच्च-यायालय'

- अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च-यायालय होगा। परंतु संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा HC की स्थापना कर सकती है (7वां संशोधन, 1956)
- इस समय भारत में कुल ~~24~~₂₅ उच्च-यायालय हैं। [25वां - अमरावती (आंध्र प्रदेश)]

अनुच्छेद 216 - 'उच्च-यायालय का गठन'

- एक मुख्य-यायाधीश + अन्य-यायाधीश (जिनको राष्ट्रपति समय-2 पर नियुक्त करेगा)
- इस प्रकार अलग-2 HC में -यायाधीशों की संख्या भी भिन्न है।

अनुच्छेद 217 - 'यायाधीशों की नियुक्ति तथा अर्हता'

नियुक्ति -

- उच्च-यायालय के मुख्य-यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा SC के मुख्य-यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार-विमर्श के पश्चात की जाती है।
- अन्य-यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य-यायाधीश, राज्यपाल तथा संबंधित HC के मुख्य-यायाधीश के परामर्श से होती है।

योग्यताएँ -

- भारत का नागरिक हो तथा 65 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- कम से कम 10 वर्ष तक -यायिक पद धारण कर चुका हो।
- HC में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

www.akashpal.com

पदावधि -

- 62 वर्ष की आयु तक
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 219 - 'शपथ ग्रहण'

- राज्य के राज्यपाल द्वारा

[प्रमुख संविधान संशोधन]

संविधान संशोधन	वर्ष	प्रभावित अनुच्छेद & अनुसूची	संशोधित विषय
प्रथम	1951	अनु. 31, 32 तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गयी।	भूमि सुधार एवं -यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 10वीं सूची में स्थान मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक हित में सीमित किया।
लेहवा	1962	371-A जोड़ा गया	नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं विशेष उपबंध राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया।
अगरह	1966	-	सिंधी भाषा शामिल
21वाँ	1967	आठवीं अनुसूची	लोकसभा सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545
31वाँ	1973	81, 330, 332	सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
36वाँ	1975	371-F जोड़ा गया	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, लोकसभा अथवा के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती
39वाँ	1975	-	प्रस्तावना में उशब्द (समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, अखंडता) मूल कर्तव्य जोड़ा गया (51A)
42वाँ (मिनी संविधान)	1976	प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची में - 31 D, 32A, 39A, 43A, 48A, भाग IVA, 51A, 73A, 144A, भाग XIVA जोड़ा गया।	त्रिनिदेशक तत्वों की मूल अधिकार पर सर्वोच्चता स्थापित संविधान को -यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। वन, कृषि, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता।
44वाँ	1978	19, 22, 30, 38, 74, 77, 165, 123, 132, 166, 172, 19(1)(F) निष्कासित 300A जोड़ा गया	संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त करके कानूनी अधिकार लोकसभा, विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष (पुनः) आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति & उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता
52वाँ	1985	10वीं अनुसूची जोड़ी गयी	पल-बदल रोकने के लिए प्रावधान
53वाँ	1986	प्रथम अनुसूची	मिजोरम को राज्य का दर्जा (371 G)
55वाँ	1986	प्रथम अनुसूची	अरुणाचल प्रदेश राज्य बना
56वाँ	1987	भाग 22	गोआ को राज्य का दर्जा
61वाँ	1989	-	मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
69वाँ	1991	-	दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा 40 सदस्यों वाली विधान सभा

आवश्यक सूचना  

यह केवल Sample Notes है यदि आप अपने विषय के Complete Notes प्राप्त करना चाहते है तो हमें वाट्सएप कर सकते है दोस्तों नोट्स बनाने में समय लगता हैं इसलिए Free में उपलब्ध कराना संभव नहीं, बहुत कम मूल्य में आपको नोट्स वाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे नोट्स में Handwriting व Content का विशेष ख्याल रखा गया है

यदि आप इच्छुक है तो हमें वाट्सएप कर सकते है

WhatsApp- 8887120469

SKY EDUCATION

- ❖ Daily Newspaper & Current Affairs
- ❖ Handwriting Notes & Online Test
- ❖ Absolutely Free Material
- ❖ आप सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित स्पेशल पीडीएफ फाइल के लिए अभी ज्वाइन

CLICK NOW



SKY EDUCATION

यदि आप हमारे वाट्सएप ग्रुप 'Sky Education' में ऐड होना चाहते हैं तो हमें Join Me टाइप कर 9696879263 पर वाट्सएप कर दीजिए आपको तत्काल ग्रुप में ऐड कर दिया जायेगा !

- ◆ **Daily Newspaper & Current Affairs**
- ◆ **Special PDF & Handwriting Notes**
- ◆ **Online Test & Quiz**
- ◆ **All Competition Exam**
- ◆ **Group Fees- 0 ₹**

बस आप अपनी मंजिल तक पहुंच जायें यही हमारा लक्ष्य है यही हमारी खुशी है- आकाश पाल